5 डॉ. मनमोहन सिंह ने दी थी आर्थिक गति

6 तकनीक के क्षेत्र में किया कमाल

7 शराब की तस्करी, एक गिरफ्त में

RNI-MPBIL/2011/39805

निष्पक्ष और निर्भीक साप्ताहिक

जगत प्रवाह

वर्ष : 15 अंक : 34 प्रति सोमवार, 30 दिसंबर 2024 मूल्य : दो रुपये पृष्ठ : 8

मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की जनता के पैसों को हवाई खर्चों और प्लेन खरीदने में किया जा रहा है बर्बाद

मध्यप्रदेश में "जनकल्याण अभियान पर्व" की जगह "मुख्यमंत्री स्व-कल्याण पर्व" मनाना चाहिए

आज मध्यप्रदेश की वित्तीय स्थिति काफी दयनीय है, किन्तु वित्तीय व्यय को सीमित करने की जगह मुख्यमंत्री अपनी विलासिता के लिए खर्च कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में ज्यादातर विमानन विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहा है। फिलहाल मुख्यमंत्री ही विमानन विभाग के मंत्री भी हैं। बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश की

क्या मुख्यमंत्री ने अपने निजी कार्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रदेश में हवाई यात्रा का बुना जाल?

क्या मुख्यमंत्री ने अपने निजी कार्यों और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रदेश में हवाई यात्रा का बुना जाल?

कवर स्टोरी

-विजया पाठक

इतनी बुरी माली हालत के बाद मुख्यमंत्री ने पिछले एक साल में फिजूलखर्ची कर जनता के पैसों में आग क्यों लगा रहे है। प्रदेश में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, रीवा, खजुराहो और एक दो शहरों को छोड़कर मध्यप्रदेश सरकार द्वारा खरीदे गए 233 करोड़ के चैलेंजर-3500 बॉम्बार्डियर प्लेन, प्रदेश के ज्यादातर हवाई पट्टियों पर उतर ही नहीं पाएगा। टेक्निकली इन हवाई पट्टियों का आकार बॉम्बार्डियर प्लेन को लैंड कराने लायक ही नहीं है। (शेष पेज 2 पर)

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेता कवासी लखमा पर कसा ईडी का शिंकजा

सीबीआई और ईडी की जांच में घिरे लखमा से प्राप्त हो सकते हैं बघेल के भ्रष्टाचारों के दस्तावेज

-विजया पाठक

छत्तीसगढ़ दिन प्रतिदिन ईडी और आयकर विभाग के अधिकारियों का मानो एक घर जैसा हो गया है। आये दिन आयकर विभाग के अफसर यहां भूपेश बघेल सरकार और उनके मंत्रियों द्वारा किये गये भ्रष्टाचारों का पर्दाफाश करने के लिये दबिश देती रहती है। इसी क्रम में अब भूपेश बघेल सरकार में अहम पद पर रहे पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के घर ईडी ने छापेमार कार्रवाई की है। इस छापेमार कार्रवाई को राजनैतिक विश्लेषक भूपेश बघेल के इशारे पर हुये घोटाले को बघेल सरकार का पाप बता रहे है। इस पूरे मामले में अब एक नया पेंच आया कि अभी तक जहां इसे स्थानीय जांच एजेंसी केस को सौंप कर रही थी वहीं अब इस पूरे मामले ईडी की एंट्री हो चुकी है।

बघेल सरकार में रहे हैं आबकारी मंत्री

ईडी ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक कवासी लखमा के घर पर छापा मारा है, इसके अलावा उनके बेटे समेत 7 जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा ईडी के अधिकारी और करीब 100 जवान शामिल हैं। कवासी लखमा पर आरोप है कि 2020 से 2022 तक जब छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री थे, तब उन्हें हर महीने 50 लाख रुपये कमीसन के रूप में दिये जाते थे। पूर्व मंत्री लखमा लगातार अपने बयानों को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब लखमा पर ईडी ने छापा मारा हो, इसके पहले भी ईडी ने छापेमार कार्रवाई की थी। इस बार उनके बेटे के घर समेत 7 जगहों पर ईडी ने छापा मारा है। (शेष पेज 2 पर)

कौन बनेगा छत्तीसगढ़ का डीजीपी

-विजया पाठक

जल्द ही छत्तीसगढ़ को नया पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) मिलने वाला है। नक्सली मूवमेंट के कारण छत्तीसगढ़ राज्य सेंसिटिव माना जाता है, ऐसे में सरकार को यह तय करना है कि वो किसी योग्य को कुर्सी पर बिठाती है या किसी अयोग्य को। किसी भी प्रदेश की प्रगति के लिए बहुत सारे कारण जिम्मेदार होते हैं। बेहतर रोजगार, उन्नत स्वास्थ्य एवं कृषि सेवाएं, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, भय और अपराध मुक्त माहौल। छत्तीसगढ़ राज्य बाकी सारे पैमानों पर तो बेहतर कार्य कर रहा है लेकिन पिछले कुछ सालों में पूरा प्रदेश गंभीर रूप से अपराध से ग्रस्त हो चुका है। अपराधियों के हौसले बहुत बढ़े हुए हैं और पुलिस प्रशासन सुस्त पड़ा हुआ है। ऐसे समय में पुलिस महकमे की

सरकार देगी किसी योग्य को कुर्सी

या किसी अयोग्य को नवाजेगी डीजीपी का पद?

जिम्मेदारी के लिए नए हाथों का तलाशा जाना अपने आप में एक ज्वलंत चर्चा का विषय हो गया है। वर्तमान पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा को अगस्त में छह माह का एक्सटेंशन देने के बाद उनका कार्यकाल फरवरी 2025 में पूर्ण हो जाएगा। (शेष पेज 3 पर)

मुख्यमंत्री बनते ही प्रदेश की जनता के पैसों को हवाई खर्चों और प्लेन खरीदने में किया जा रहा है बर्बाद

(पेज 1 से जारी)

सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिव विमानन कलेक्टरों द्वारा हवाई पट्टियों का आकार बढ़ाने के लिए दबाव मोहन यादव के निर्देश पर बना रहे हैं। कुछ कलेक्टरों द्वारा असमर्थता दिखाने के बाद वल्लभ भवन से गूगल अर्थ के माध्यम से खाली जगह दिखाई जा रही है ताकि पट्टियों का निर्माण लिए गए प्लेन के माफिक हो सके। मेरे द्वारा विमानन विभाग से सूचना के अधिकार पत्र क्रमांक एफ-43/आर.टी.आई./662 दिनांक 01-07-2022 से प्राप्त जानकारी अनुसार 2021 में तब के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शासकीय/किराए से लिए हुए प्लानों से कुल 45-50 यात्राएं की। जबकि प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अकेले ही मुख्यमंत्री बनने के बाद एक साल में 486 से अधिक यात्राएं कर डाली हैं, इनमें से केवल उज्जैन-इंदौर के लिए मोहन यादव द्वारा 150 से अधिक बार हवाई यात्राएं की। इसका मतलब मुख्यमंत्री उज्जैन शहर से भोपाल अप-डाउन करते थे।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एक तरफ जहां देश में जनसेवक के रूप में कार्य कर देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के कारनामों का प्रमाण कांग्रेस विधायक द्वारा विधानसभा में पूछे गये एक सवाल के जबाव में मिला। जिसमें प्रदेश के नगरीय विमानन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री व मंत्री सहित आईएएस अफसरों ने एक वर्ष में लगभग 32 करोड़ रुपये से अधिक की हवाई यात्रा की हैं। यानि प्रतिदिन मोहन सरकार ने लगभग 09 लाख रुपये केवल हवाई यात्रा पर ही उड़ा दिये हैं। यही नहीं 365 दिन के एक वर्ष में मोहन सरकार के कार्यकाल में कुल 666 हवाई यात्रायें हुई जिसमें से 486 से अधिक यात्रा तो सिर्फ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अकेले ही कर ली। बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश सरकार के मुखिया और नुमाइंदों द्वारा की गई इन यात्राओं का औचित्य क्या निकला। क्या परिणाम प्राप्त हुये हैं इन यात्राओं के इस बारे में जानकारी प्रदेश की मोहन सरकार ने विधानसभा पटल पर क्यों नहीं रखी। विभाग के सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सबसे अधिक यात्रा सिर्फ भोपाल से इंदौर और उज्जैन के बीच में की है। संख्यावार देखा जाये तो लगभग एक वर्ष में उन्होंने 150 से अधिक वार सिर्फ भोपाल-उज्जैन के बीच यात्रा की। जिसमें वे कभी सुबह चाय पीने, तो कभी दोपहर का लंच करने और कभी रात में परिवार के साथ भोजन करने भोपाल से उज्जैन सीधे हवाई मार्ग से पहुंचते। जनता के टैक्स के पैसों का पिछले एक वर्ष में मोहन सरकार ने किस तरह से बंटाधार किया है यह आंकड़ें इस बात का परिणाम है।

ऐशो आराम की जिंदगी काट रहे मुख्यमंत्री

प्रदेश का मुखिया बन ऐश की जिंदगी काटने वाले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का तरीका बिल्कुल राजशाही है। वे हवाई जहाज से नीचे यात्रा नहीं करते और बगैर 25 गाड़ियों के काफिले के कहीं दौरे पर नहीं जाते। जबकि देखा जाये तो उनके इस काफिले में महज पांच गाड़ियों की आवश्यकता होती है लेकिन वर्तमान में 20 से अधिक गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती दिखाई देती हैं जिसका कोई विशेष औचित्य नहीं। यह सिर्फ जनता के पैसों की बर्बादी और राज्य के बजट को समाप्त करने की जुगत है। मुख्यमंत्री यादव केवल अपना विकास चाहते हैं इसलिये वे अपने किसी ऐशो आराम में कमी नहीं होना देना चाहते हैं।

233 करोड़ से नया प्लेन खरीदने की योजना

प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री के अनुसार मोहन सरकार कनाड़ा की एक विशेष कंपनी से नया जेट प्लेन चैलेंजर-3500 खरीदने जा रही है। इसके लिये मोहन यादव ने प्लानिंग करके पहले विधानसभा में बजट पास कराया और फिर कैबिनेट में सहमति पत्र जारी कर कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर इंक को नये विमान का वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया है। यानि मध्यप्रदेश सरकार ने कनाडा की कंपनी बॉम्बार्डियर इंक के चैलेंजर 3500 मॉडल को 233 करोड़ रुपये में खरीदने का फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश सरकार का हवाई जहाज छह मई 2021 को ग्वालियर मैं लैंडिंग के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। कंपनी ने उस विमान को 'बियॉन्ड रिपेयर' करार दिया। यानी अधिकारियों की लापरवाही के कारण उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी।

अब हवाई पट्टी चौड़ीकरण का दिया आदेश

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बगैर सोचे-समझे कनाडा की इस कंपनी से नया प्लेन खरीदने का आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन जब अधिकारियों ने इसकी पड़ताल की तो मालूम चला कि यह प्लेन भोपाल, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर के अलावा प्रदेश के किसी भी जिले की हवाई पट्टी पर उतरने में सक्षम नहीं है। जब विमानन विभाग के अधिकारियों ने यह जानकारी मुख्यमंत्री तक पहुंचाई तो मुख्यमंत्री ने प्रदेश की हवाई पट्टी चौड़ीकरण का शगूफा छोडा और प्रदेश में करोड़ों रुपये सिर्फ अब हवाई पट्टी के चौड़ीकरण में खर्च किये जा रहे हैं। यही नहीं मंत्रालय के एक उच्च स्तरीय अफसर ने नाम न छापने की शर्त पर यह जानकारी दी कि कई जिलों में हवाई पट्टी चौड़ीकरण के लिये अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता पड़ रही है जिसके अधिग्रहण के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कलेक्टरों पर दवाब डाल रहे हैं। जबकि कुछ जिलों के कलेक्टर ने तो इस कार्य को करने से मना ही कर दिया।

क्या पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा भी है सिर्फ दिखावा?

मोहन यादव द्वारा जून माह में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, खजुराहो, रीवा और सिंगरौली के बीच पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा चालु की। इस सेवा का संचालन निजी चालकों को दिया गया। कई रूट्स में यह सेवा फ्लॉप रही बाकी इनकी सर्विस काफी खराब रही है। कई मौकों में कन्फर्म टिकट होते हुए भी वीआईपी के कारण यात्रियों को ट्रैवल नहीं करने दिया जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यहां भी बिना कोई ठोस विचार या ग्राउंड वर्क किए बगैर सिर्फ अपनी विलासितापूर्ण जीवनशैली के अनुरूप ही ऐसी स्कीम प्रदेश में लागू कर दी। निजी चालकों को भी मनमाफिक स्वतंत्रता देने के पीछे कहीं कोई "उपकृत सेवा" तो नहीं, इसकी जांच की जानी चाहिए।

प्रदेश पर भारी पड़ रही है मुख्यमंत्री मोहन यादव की महंगी लाइफस्टाइल

आज मध्यप्रदेश 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कर्जे में हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव अपनी सुख सुविधाओं के लिये हजारों करोड़ों रुपये खर्च कर प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था को चौपट करने में जुटे हुये हैं। मुख्यमंत्री की इसी तरह की वित्तीय अनिमित्ताओं के कारण प्रदेश पर पौने चार करोड़ लाख करोड़ से अधिक का कर्ज हो गया है। यानि प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति कर्ज में डूबा हुआ है। जाहिर है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सत्ता में आने के बाद दूसरी बार बाजार से पांच हजार करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। 2500-2500 करोड़ रुपये की दो किश्तों में कर्ज लिया गया है। पहली किश्त का कर्ज 11 साल में और दूसरी किश्त का कर्ज 19 साल में चुकाया जाएगा।

इस साल कर्ज की कुल राशि 40,500 करोड़

इस साल 35 हजार 500 करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। पिछले वर्ष 23 जनवरी को 2500 करोड़, फरवरी माह में 13 हजार करोड़, 26 मार्च को पांच हजार करोड़, अगस्त माह में 10 हजार करोड़ और 24 सितंबर को पांच हजार करोड़ इस तरह आठ बार कुल 35 हजार 500 करोड़ रुपये कर्ज ले चुकी है। उल्लेखनीय है कि अब तक राज्य सरकार 3.75 लाख करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज ले चुकी है। वहीं, मध्यप्रदेश के कुल बजट की बात करें तो यह 3.65 लाख करोड़ रुपये का है, लेकिन इससे अधिक मध्यप्रदेश सरकार पर कर्ज है।

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी नेता कवासी लखमा पर कसा ईडी का शिंकजा

(पेज 1 से जारी)

इस मामले में कुछ समय पहले ही छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने शराब घोटाला मामले को लेकर बड़ा फैसला किया था। सरकार ने इसकी आगे की जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) को सौंप दी है।

इन जगहों पर मौजूद ईडी

यह छापेमारी छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ी हुई है। जिसकी जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। पूरा मामला कांग्रेस सरकार के समय का बताया जा रहा है। फिलहाल ईडी के अधिकारी दोनों नेताओं से पूछताछ कर रहे हैं। वहीं ईडी की रेड से हड़कंप मच गया है। ईडी की टीम जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश कवासी और सुकमा नगर पालिका अध्यक्ष जगन्नाथ राजू साहू के घर पर मौजूद है। छापेमार कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी मौजूद है।

शराब घोटाले से है कनेक्शन

छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले मामले में एसीबी में हुई एफआईआर के बाद ईडी जांच कर रही है। दर्ज एफआईआर में 2 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले की बात कही गई है। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि तत्कालीन भूपेश सरकार के कार्यकाल में कई नेता और अफसर अवैध सिंडिकेट के जरिए शराब घोटाले को अंजाम दे रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पूरा सिंडिकेट सरकार के इशारों पर ही संचालित हो रहा था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी इसकी जानकारी थी। एफआईआर में इस बात का भी जिक्र है कि घोटाले के अवैध कमीशन का बड़ा हिस्सा आबकारी मंत्री कवासी लखमा के पास भी जाता था। 2161 करोड़ के शराब घोटाले के मामले में एसीबी ने 70 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था। एफआईआर में तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा का नाम शामिल है। जिन्हें हर महीने 50 लाख दिया जाता था। फिलहाल ईडी की कार्रवाई जारी है और शराब घोटाले से जुड़े दस्तावेज पैसों के लेन-देन की जानकारी सहित अन्य जानकारियां खंगाजी जा रहा है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने दी कर्मचारियों को सौगात

-आनंद शर्मा

जगत प्रवाह,रायपुर।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कर्मचारियों के हितों को ध्यान रखते हुए मासिक भत्तों में संशोधन किया गया है। इससे कर्मचारियों का कार्य प्रदर्शन बेहतर हो सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के विभिन्न सरकारी कर्मचारियों के यात्रा भत्ते की मासिक दरों में संशोधन किया है। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी किया गया है। राज्य सरकार द्वारा संशोधित भत्ते के लिए राजस्व निरीक्षकों, विक्रय अमीन, सहायक ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी (ग्राम सेवक), सहायक विकास विस्तार अधिकारी, पशु चिकित्सा के

क्षेत्र सहायक,लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के हैंड पंप तकनीशियनों को शामिल किया गया है। उनको वर्तमान दर 350 रुपए प्रति माह को संशोधित कर 1200 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। इसी तरह जिला और तहसील स्तर के राजस्व विभाग के भृत्य एवं जमादार,वन विभाग और राजस्व विभाग के चेन मैन, न्यायिक एवं वाणिज्यक कर विभाग के प्रोसेस सर्वर तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यरत पटवारियों के वर्तमान दर 300 रुपए प्रति माह में संशोधन कर 1000 रुपए प्रति माह यात्रा भत्ता दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा यह संशोधन कर्मचारियों के कामकाज को ध्यान में रखते हुए किया गया है, ताकि उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। आदेश के अनुसार यात्रा भत्ता के अन्य शर्तें एवं नियम यथावत रहेंगे। यह संशोधन आदेश दिनांक से प्रभावशील होगा।

(जगत फीचर्स)

छत्तीसगढ़ डीजीपी के पद के लिए पवन देव सबसे उपयुक्त, एसआरपी कल्लूरी, जीपी सिंह भी हो सकते हैं राइट चॉइस

(पेज 1 से जारी) प्रदेश में चरमराती सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए नए पुलिस महानिदेशक का चुनाव सम्पूर्ण प्रदेश के लिए नितांत महत्वपूर्ण मुद्दा है। वैसे भी छत्तीसगढ राज्य का पुलिस महानिदेशक का चयन एक और दृष्टि से बहुत जटिल है क्योंकि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने वर्ष 2026 में सम्पूर्ण देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का संकल्प लिया है। छत्तीसगढ भी देश के नक्सल प्रभावित राज्यों में से एक है जहाँ नक्सलवाद ने प्रदेश के विकास में पुरजोर कुठाराघात किया हुआ है। ऐसे में प्रदेश में नए पुलिस महानिदेशक की आमद बहुत सारे सवालों के जवाब के साथ होगी। अभी तक अगले पुलिस महानिदेशक की क़तार में तीन नाम प्रमुख रूप से सामने आ रहे हैं जो हैं पवन देव, हिमांशु गुप्ता और अरुण देव गौतम। अगर वरिष्ठता की बात करें तो 1992 बैच के पवन देव सबसे आगे हैं। उनके बाद आते हैं अरुण देव गौतम और फिर नंबर आता है 94 बैच के हिमांशु गुप्ता का। वैसे सीनियरिटी में देखा जाए तो पवन देव राज्य के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर हैं, उनके अलावा जीपी सिंह और एसआरपी कल्लूरी भी पद पर फिट बैठते हैं। दो नाम और है जिनमें से एक हिमांशु गुप्ता बड़े विवादित आईपीएस रहे हैं जिन पर सविता खंडेलवाल और उनके बेटे को लेकर तौहमत भी लगी थी। अरुण देव गौतम का भी नाम डीजीपी पद के लिए गया है, पर वो काफी इनेक्टिव/पैसिव अधिकारी रहे हैं। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य में अभी एक तेजतर्रार डीजीपी चाहिए जो कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के विजन के अनुरूप राज्य में नक्सलवाद खत्म कर सके। छत्तीसगढ प्रदेश में एक विजनरी, साहसी और बेहतर रणनीतिकार पुलिस महानिदेशक की दरकार है जो ना सिर्फ़ अपराध और अपराधियों पर नकेल कस सकें बल्कि नक्सलवाद को समूल ख़त्म करने में अपने अनुभव और रणनीति का उपयोग कर प्रदेश को भय मुक्त बनाने में सफल हो सकें। आईये जानते हैं डीजीपी की रेस में कौन-कौन है दावेदार-

छत्तीसगढ़ डीजीपी के लिए सबसे उपयुक्त अधिकारी

पवन देवः पवन देव डीजीपी के दावेदारों में सबसे प्रमुख हैं। पवन देव छत्तीसगढ़ में भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों में शामिल हैं। प्रदेश को 2026 तक नक्सल मुक्त करने का जो वादा है उसमें पवन देव की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। डीजी पुलिस अशोक जुनेजा के बाद बैच वाइज सीनियरिटी में पवनदेव 1992 बैच में सबसे ऊपर हैं। जुनेजा का कार्यकाल पूरा होने से पहले सरकार ने सीनियर आईपीएस अधिकारियों के नाम शॉर्टलिस्ट करके केन्द्रीय गृह मंत्रालय को गोपनीय प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव में डीजीपी की रेस में सबसे पहले पवन देव का नाम चल रहा है। उज्जैन में 1995 में (पिंजारवाड़ी) महाकाल मंदिर से लगा हुआ था। इन्होंने उज्जैन में इस एरिया को बंद करवाया गया था। जो आज तक बंद है। अबूझमाड़ में छापा मारकर नक्सली नेक्सेस को नष्ट किया। 1998 में कांकेर नक्सलियों की केन्द्रीय समिति की बैठक पर छापा मारा, जो कि अविभाजित मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ का एक एकलौता मामला रहा है। इसी दौरान 5000 नक्सलियों का समर्पण भी पोस्टिंग के दौरान हुआ। 2007 में छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के कैंप पर छापा मारा गया। यह राज्य बनने के बाद नक्सलियों के खिलाफ पहली बड़ी कार्यवाही थी। इनके मार्गदर्शन में एसपी राजनांदगांव रहते हुए की गई और इसमें एक महिला नक्सली मारी भी गई। 2005 में नक्सलियों के खिलाफ सूचना संकलन के लिए (SIB) स्पेशल इंटेलिजेंस ब्रस्क का गठन किया गया। पुलिस अधीक्षक रेल के पद पर रहते हुए अतिरिक्त प्रभार के साथ इस ब्रांच के मुखिया का पदभार भी संभाला। उनका आईपीएस के रूप में कार्यकाल साफ-सुथरा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य को उनके जैसा तेज तर्रार डीजीपी की आवश्यकता है।

आईपीएस पवन देव को वर्ष 2011 में राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किया गया। राजनांदगांव नक्सली काउंटर में राज्य शासन द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इन्होंने नक्सलियों के प्रिंट यूनिट (प्रिंटिंग प्रेस जिसमें अपना साहित्य छपवाते हैं) बंद करवाया। 2007 में जब पवन देव डीआईजी कांकेर थे तब फिर से नक्सली प्रिंट यूनिट पर छापा मारकर सभी साहित्य को नष्ट किया गया। 2008-2010 DIG (SIB) रहते हुए नक्सली इंटेलिजेंस ऑपरेशन किए गए। आधुनिक उपकरण किए गए। आधुनिक उपकरण से लैस कर सारे ऑपरेशन किये गए। आईजी प्रशासन 2011 में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संपूर्ण भारत में पहली बार आयोजित की गई। अन्य तरीकों को भी Adopt किया गया जो अन्य राज्यों के लिए मॉडल साबित हुआ। वर्ष 2018 में Director प्राजिक्यूशन रहते हुए विभाग हेतु ISO सर्टिफिकेट प्राप्त किया गया।

आईपीएस पवन देव छत्तीसगढ़ कैडर के 1992 बैच के आईपीएस हैं। वे मूलतः बिहार के रहने वाले हैं। उनका जन्म 16 जुलाई 1968 को हुआ है। उन्होंने बीई मैकेनिकल की डिग्री लेने के बाद यूपीएससी की तैयारी की और आईपीएस बने। आईपीएस की नौकरी करते हुए बिलासपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलबी की डिग्री भी प्राप्त की।

एसआरपी कल्लूरीः कल्लूरी ने डीजीपी बनने की 30 साल की सेवा की मियाद पूरी कर ली है। कल्लूरी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नही हैं। कोई अनैतिक कार्यों का आरोप नही लगा। कल्लूरी बलरामपुर में जब एसपी थे तब उन्होंने पूरे नक्सलियों का सफाया कर दिया था। छत्तीसगढ़ की सीमा गढ़वा क्षेत्र से उन्होंने नक्सलियों सफाया किया। पहले कल्लूरी डीआईजी दंतेवाड़ा बस्तर रेंज के आईजी बने तब सबसे ज्यादा नक्सलियों का सफाया इनके कार्यकाल में हुआ।

जीपी सिंहः ज्ञात हो कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जीपी सिंह के ख़िलाफ़ आय से अधिक संपत्ति, राजद्रोह और ब्लैकमेलिंग आदि मामलों में कार्रवाई की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि उन्हें परेशान करने के लिए झूठे मामलों में फंसाया गया था और उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं हैं। तत्कालीन भूपेश सरकार ने उन्हें राजनीतिक षड़यंत्र के तहत फंसाया था। उनके खिलाफ किसी भी मामले में कोई भी साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने उन्हें किसी भी मामले में आरोपी नहीं माना। जीपी सिंह का सम्पूर्ण सेवाकाल बेदाग रहा है। वापिस वर्दी में आते ही जीपी सिंह डीजीपी की रेस में भी शामिल हो गए हैं। 1994 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के अधिकारी जीपी सिंह डीजीपी रेस में शामिल सभी अधिकारियों से वरिष्ठता में कम हैं लेकिन अपनी तेज तर्रार, बेबाक और दबंग छवि के कारण वे पद के लिए उपयुक्त माने जा रहे हैं। यक़ीनन जीपी सिंह की बहाली ने डीजीपी चुनाव को अत्यंत रोमांचक बना दिया है। जीपी सिंह एक तेजतर्रार आईपीएस अधिकारी हैं और पद के लिए उपयुक्त भी हैं। यदि प्रदेश में जीपी सिंह डीजीपी बनते हैं तो सरकार का यह कदम न्यायोचित होगा।

डीजीपी पद के लिए अनुपयुक्त अधिकारी

अरुण देवः अरुण देव हमेशा से बैक फुट पर खेलते आए हैं, 1995 में अपनी पहली पोस्टिंग सीएसपी उज्जैन में थी। 1992 बैच के अरुण देव गौतम सितंबर 2027 में सेवानिवृत होंगे। लंबे कार्यकाल को देखते हुए पुलिस मुखिया बनाने पर विचार किया जा रहा है। लेकिन वह किसी भी काम को हाथ में नही लेते हैं और बचते हैं। रिस्पांसबिलिटी और दायित्व बिलकुल नही लेना चाहते। आज के परिपेक्ष्य में जब अमित शाह ने राज्य से 2026 तक नक्सलवाद के सफाए की घोषणा की है और निश्चित तौर पर अगर इसमें वो असमर्थ रहते हैं तो 2028 की विधानसभा चुनावों में यह एक प्रमुख मुद्दा रहेगा, अरुणदेव गौतम इस पद के लिए फिलहाल अनुपयुक्त नजर आ रहे हैं।

हिमांशु गुप्ताः हिमांशु गुप्ता का नाम चर्चा में आने के बावजूद उनकी नियुक्ति को लेकर कुछ विवाद भी हैं। सविता खंडेलवाल से उनके रिश्ते को लेकर खूब आरोप लगे जिसे लेकर तत्कालीन सरगुजा रेंज पुलिस महानिरीक्षक हिमांशु गुप्ता ने सविता खंडेलवाल को अम्बिकापुर सखी सेंटर के माध्यम से पागल घोषित करके रायपुर इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंस में भेज दिया। डॉक्टर ने स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज कर दिया। हिमांशु गुप्ता एक डरपोक अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं।

पति-पत्नी के विवाद में हिमांशु गुप्ता हुए थे बदनाम!

छत्तीसगढ़ के सबसे विवादित आईपीएस अफसर मुकेश गुप्ता के खास हैं हिमांशु गुप्ता

सरगुजा रेंज के आईजी हिमांशु गुप्ता अचानक चर्चा में आ गए थे। चर्चा भी ऐसी-वैसी नहीं बल्कि उनके चरित्र पर सवाल उठाने वाली थी। मामला धमतरी का था। हिमांशु गुप्ता जब धमतरी एसपी थे तब हिमांशु के खिलाफ एक माह तक सविता खण्डेलवाल ने धरना दिया था। तो गुप्ता ने उसे पागलखाने भिजवा दिया था एवं उनके लड़के को बाल सुधार गृह में भिजवाया था। जबकि वह पागल नही था। सविता खंडेलवाल का कहना था कि वे पिछले कई वर्षों से घरेलू हिंसा का शिकार हैं। उन्होंने धमतरी कलेक्टर, एसपी से लेकर सीएम तक गुहार लगाई है। लेकिन उन्हें कहीं से मदद नहीं मिली। आखिरकार सविता खंडेलवाल ने एक महीना तक अपनी गुहार सरकार से लगाते हुए धरना दिया था। आखिरकार सविता ने सिस्टम से दुखी होकर हिमांशु गुप्ता एवं एक और सीनियर आईपीएस अफसर पर आरोप लगाकर खुदकुशी कर ली थी।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने श्री कुशाभाऊ ठाकरे और सुंदरलाल पटवा की पुण्यतिथि तथा अरुण जेटली की जयंती पर किया नमन

-शशि पाण्डेय

जगत प्रवाह.रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 28 दिसंबर को स्वर्गीय श्री कुशाभाऊ ठाकरे और श्री सुंदर लाल पटवा की पुण्य तिथि तथा श्री अरुण जेटली की जयंती पर उन्हें नमन किया है। मुख्यमंत्री साय ने कुशाभाऊ ठाकरे जी के देश के लिए योगदान को याद करते हुए कहा है कि कुशाभाऊ जी नैतिकता, आदर्श व सिद्धांतों के प्रकाश स्तंभ थे। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण अटूट था। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने समाज के प्रत्येक वर्ग की सुख-समृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से काम किया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे जी जैसे निष्काम कर्मयोगी के विचार और जीवनमूल्य हमें सदैव देश सेवा के लिए प्रेरित करते रहेंगे। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पद्मविभूषण स्वर्गीय श्री अरूण जेटली की 28 दिसंबर को जयंती पर उन्हें नमन किया है। उन्होंने कहा कि जेटली जी ने भारत के वित्त, रक्षा, कॉरपोरेट मामले, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण विभागों को कुशलता से संभाला और देश के विकास को नई गति दी। उन्होंने देश की आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जेटली जी को वित्तीय मामलों का गूढ़ जानकार माना जाता था। उन्होंने भारत में आर्थिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली जी का देश के विकास में दिया गया अमूल्य योगदान हमेशा याद किया जाएगा। इसी तरह मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अविभाजित मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केन्द्रीय कैबिनेट मंत्री पद्म विभूषण सुन्दर लाल पटवा की 28 दिसंबर को पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। साय ने कहा कि पटवा जी अनुशासनप्रिय व्यक्ति के रूप में जाने जाते थे। सौम्य व्यक्तित्व, कुशल संगठन क्षमता से युक्त, ओजस्वी वक्ता और विभिन्न जनसमस्याओं को उठाने वाले जुझारू नेता के रूप में पटवा जी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। उन्होंने समाज के हर तबके के लिए काम किया और किसान हितैषी कई फैसले लिए। वे सहकारी आंदोलन से जुड़े और अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों को संभाला। उन्होंने सहकारिता आंदोलन को जनोन्मुखी बनाया। उनके कार्यकाल में सहकारी संस्थाओं के माध्यम से कमजोर वर्गों, शिल्पियों और श्रमिकों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के सफल प्रयोग किये गये। श्री साय ने कहा कि पटवा जी का व्यक्तित्व और कृतित्व हमें सदैव अपने दायित्वों का उत्कृष्टतापूर्वक निर्वहन करने की प्रेरणा देता रहेगा।(जगत फीचर्स)

सम्पादकीय

संघ प्रमुख भागवत के बयान से क्यों शुरू हुई बहस?

बीते दिनों राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या में गिरावट पर अपनी चिंता व्यक्त की। उनका कहना था, "आधुनिक जनसंख्या विज्ञान कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या (प्रजनन दर) 2.1 से नीचे चली जाती है तो वह समाज पृथ्वी से लुप्त हो जाता है... इस तरह अनेक भाषाएं और समाज नष्ट हो गए ...जनसंख्या विज्ञान का कहना है कि हमें दो या तीन से अधिक बच्चे पैदा करने की आवश्यकता है। समाज को जीवित रखने के लिए संख्या महत्वपूर्ण है। जैसे ही उनका विचार मीडिया की सुर्खियों में आया, वैसे ही स्वयंभू सेकुलरवादी और वामपंथी तिलमिला उठे। संघ प्रमुख ने जिस आशंका को प्रकट किया है, उससे सार्वजनिक जीवन में सक्रिय जनप्रतिनिधियों का एक समूह परिचित तो है, लेकिन अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के कारण उसे जन-विमर्श का हिस्सा बनाने से न सिर्फ बचता है, बल्कि उसे नया रंग देने का प्रयास भी करता है। आरोप-प्रत्यारोपों को दरकिनार कर क्या हमें हकीकत को नहीं देखना चाहिए? क्या यह सच नहीं कि भारतीय उपमहाद्वीप (भारत सहित) में हिंदुओं की जनसंख्या, मुस्लिमों के अनुपात में लगातार घट रही है? क्या मजहब का भारत की एकता-अखंडता और इस राष्ट्र के शाश्वत मूल्यों— बहुलतावाद, लोकतंत्र और सेकुलरवाद के साथ सीधा संबंध है या नहीं? देश में जहां-जहां आज हिंदू अल्पसंख्यक है, उनमें से अधिकतर क्षेत्र क्या अलगाववाद से ग्रस्त नहीं? संघ प्रमुख के विचार पर त्वरित कोई राय बनाने से पहले क्या इन सवालों के जवाब ईमानदारी से खोजने चाहिए।

क्या यह सत्य नहीं कि ब्रिटिशकालीन भारत, जनसांख्यिकीय में आए परिवर्तन के कारण ही विभाजित हुआ था? इस त्रासदी में जिन दो मुल्कों पाकिस्तान और बांग्लादेश का जन्म हुआ, वह घोषित रूप से इस्लामी है। अपने वैचारिक अधिष्ठान के अनुरूप इन दोनों ही देशों में हिंदू, बौद्ध और सिख आदि अल्पसंख्यकों के लिए न तो कोई स्थान है और न ही उनके मानबिंदु (मंदिर-गुरुद्वारा सहित) सुरक्षित। विडंबना है कि सिंधु नदी, जिसके तट पर हजारों वर्ष पूर्व ऋषि परंपरा से वेदों की रचना हुई— उस क्षेत्र में आज उनका नाम लेने का कोई नहीं बचा है।

भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक 'असुरक्षित' कौन है? विश्व के इस भूखंड में कुल मिलाकर 180 करोड़ लोग बसते है, जिसमें भारत 140 करोड़, पाकिस्तान 23 करोड़ और बांग्लादेश की आबादी 17 करोड़ है। 180 करोड़ में 112 करोड़ हिंदू है, जबकि मुस्लिम 62 करोड़ से अधिक मुस्लिम। विभाजन से पूर्व, इस भू-भाग की कुल आबादी में हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन अनुयायियों का अनुपात 75 प्रतिशत, तो मुस्लिम अनुपात 24 प्रतिशत था। स्वाधीनता से लेकर आज तीनों देशों में हिंदू-सिख-बौद्ध-जैन घटकर 62 प्रतिशत रह गए है, जबकि मुस्लिम बढ़कर 34 प्रतिशत हो गए।

यदि हिंदू बहुल भारत का एक तिहाई हिस्सा अगस्त 1947 में इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बन गया, तो 21वीं सदी से पहले ईसाई बहुल सर्बिया का हिस्सा रहे मुस्लिम बहुल कोसोवो ने 2008 में स्वयं को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर लिया। संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्यों में से 104 देशों ने कोसोवो को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता भी दी है।

सियासी गहमागहमी

अपने ही विभाग की पोल खोल बैठे स्कूल शिक्षा मंत्री

मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने ही विभाग की पोल खोल दी। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों से प्राइवेट स्कूल बेहतर हैं। मैं 500 शिक्षकों को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं जो स्कूल नहीं जाते। ऐसे शिक्षक स्कूल किराए से लगाते हैं। 100 तो मेरे जिले में ही हैं। मेरे गांव के मिडिल स्कूल में 6 शिक्षक और 38 बच्चे हैं, वहीं 12वीं तक स्कूल में 900 बच्चे है। स्कूल शिक्षा मंत्री के इस बयान के बाद मोहन सरकार के खेमे में चहलकदमी मच गई है। स्कूल शिक्षा को मजबूती देने संबंधी बड़े-बड़े दावे करने वाली भाजपा सरकार की करतूतों से उनके ही मंत्री ने पर्दा उठा दिया है। हालांकि उदय प्रताप के इस बयान के बाद संघ के पदाधिकारी खासे नाराज हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री तक इस बयान पर नाराजगी व्यक्त करने संबंधी एक शिकायती आवेदन भी पहुंचा दिया है। अब देखने वाली बात यह है कि मोहन सरकार इस पूरे मामले पर क्या एक्शन लेती है।

आखिर सौरभ शर्मा का रहनुमा कौन है?

मध्य प्रदेश परिवहन विभाग के सिपाही सौरभ शर्मा को लेकर एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक सौरभ शर्मा ने अपनी पत्नी को 14 लाख का लहंगा नवरात्रि के दौरान गिफ्ट किया था। उसने गुजरात से ये महंगा लहंगा मंगवाया था। ईडी के हाथ इस लहंगे का बिल लगा है। इतना ही नहीं ईडी की टीम ने 7 ठिकानों से कई दस्तावेज भी जब्त किए हैं। आरोपी सौरभ शर्मा के करीबियों के बैंक अकाउंट की भी जानकारी खंगाली जा रही है। प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि सौरभ शर्मा ने अपने करीबियों के खाते से बड़ी राशि का ट्रांजेक्शन किया है। इतना ही नहीं देवास की एक फर्म को 1 साल में 7 करोड़ रुपये के ट्रांजेक्शन की भी जानकारी मिली है। लगातार जांच में सामने आ रहे इन तथ्यों को देख एक बात समझ नहीं आ रही कि एक मामूली से रिटायर्ड रक्षक का रहनुमा कौन है। वे कौन लोग हैं जो सौरभ शर्मा को इतने वर्षों से संरक्षण देते आ रहे थे। ऐसे लोगों का नाम सामने आते ही उन्हें जनता के साथ सार्वजनिक करना चाहिए।

हफ्ते का कार्टून

ट्वीट-ट्वीट

भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार आज निगमबोध घाट पर करवाकर वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है।
एक दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे, उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना और उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है।
-राहुल गांधी
कांग्रेस नेता @RahulGandhi

प्रदेश के सोयाबीन किसान एक बार फिर से अष्टाचार का शिकार बन रहे हैं। सोयाबीन की सरकारी खरीद में हर बोरे पर 400 रुपये की रिश्वत लेने के आरोप अत्यंत गंभीर हैं। इसी भ्रष्टाचार का नतीजा है कि प्रदेश में तय सीमा से आधा सोयाबीन ही MSP पर खरीदा जा सका है।
-कमलनाथ
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
@OfficeOfKNath

राजवीरों की बात

पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत को दी थी आर्थिक गति

समता पाठक/जगत प्रवाह

स्मृति शेष....

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह का 26 दिसंबर, 2024 को 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नई दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांस ली। एम्स की ओर से इस संबंध में एक पत्र जारी कर निधन की पुष्टि की गई है। उनके निधन पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत विभिन्न राजनीतिज्ञों और अलग-अलग क्षेत्र के विशेषज्ञों ने शोक जताया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह 26 दिसंबर को बेहोश हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एम्स लाया गया था। यहां उन्होंने अंतिम सांस ली है।

डॉ. मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत के गाह नामक गांव (अब पाकिस्तान में) में हुआ था। हालांकि, 1947 में देश आजाद होने के बाद उनका परिवार अमृतसर आकर बस गया। उन्होंने चंडीगढ़ स्थित पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक किया स्नातक के बाद उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर किया। वर्ष 1957 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में टॉप रैंक के साथ इकोनॉमिक्स ट्रिपोस पूरा किया। वर्ष 1962 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के नफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में पीएचडी (डीफिल) की उपाधि प्राप्त की। उनका शोध "India's Export Trends and Prospects for Self-Sustained Growth" भारत की व्यापार नीति पर एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज बना। राजनीति में आने से पहले डॉ. सिंह ने एक अर्थशास्त्री और शिक्षक के रूप में करियर बनाया। उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में किया। साथ ही, आर्थिक अनुसंधान और नीतियों पर गहन कार्य किया। कुछ समय बाद वह यूनाइटेड नेशन्स कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक से जुड़े। अपनी प्रतिभा पर उन्होंने व्यापार और विकास अर्थशास्त्र में अंतरराष्ट्रीय पहचान बनाई।

डॉ. मनमोहन सिंह मुख्य आर्थिक सलाहकार (1972-1976): प्रमुख आर्थिक निर्णयों में योगदान। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर (1982-1985): मौद्रिक नीति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। -योजना आयोग के उपाध्यक्ष (1985-1987): उन्होंने योजना आयोग के उपाध्यक्ष रहते हुए भारत की आर्थिक योजना में योगदान दिया। वर्ष 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह ने भारतीय राजनीति में कदम रखा। यह वह समय था, जब भारत भारत आर्थिक संकट से जूझ रहा था। ऐसे में तत्कालीन प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव ने उन्हें वित्त मंत्री नियुक्त किया। इस पद रहते हुए उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए। डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजारों के लिए खोलने के लिए उदारीकरण सुधार लागू किए। साथ ही, उन्होंने लाइसेंस राज समाप्त कर, निजीकरण और राज्य नियंत्रण में कमी की। डॉ. सिंह द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के साथ निर्यात को प्रोत्साहित किया गया।

डॉ. मनमोहन सिंह ने भारत के 13वें प्रधानमंत्री के रूप में लगातार दो कार्यकाल पूरे किए हैं। अपने पहले कार्यकाल 2004–2009 में उन्होंने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया। वहीं सूचना का अधिकार अधिनियम भी उनके कार्यकाल में आया। इसके अतिरिक्त उन्हें ऐतिहासिक भारत-अमेरिका असैन्य परमाणु समझौता पर हस्ताक्षर के लिए भी जाना जाता है। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि, इस दौरान उन्हें 2जी स्पेक्ट्रम घोटाला और राष्ट्रमंडल खेल घोटाले जैसे विवादों का भी सामना करना पड़ा।

उपलब्धियां और सम्मान

डॉ. मनमोह सिंह को पद्म विभूषण (1987) भारत सरकार की ओर से उन्हें भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। इसके साथ ही कैम्ब्रिज और

क्या दलितों के अत्याचार पर केन्द्रित रहा मोहन सरकार का एक साल?

कमलनाथ
(मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ नेता)

कर्ज के भरोसे चल रही सरकार

मध्यप्रदेश की डॉ. मोहन यादव सरकार का एक साल का कार्यकाल 13 दिसंबर को पूरा हो गया। अब बीजेपी इस एक साल को स्वर्णिम कार्यकाल बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है। लेकिन मोहन सरकार ने गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं, दलितों और सभी वर्गों के लोगों के लिए क्या किया है यह विचारणीय है। महिला सुरक्षा, दलित और आदिवासी सुरक्षा के मामले में मध्यप्रदेश का रिकॉर्ड और भी खराब हो गया है। स्वास्थ्य शिक्षा का हाल यह है कि मध्यप्रदेश की पहचान व्यापमं और नर्सिंग जैसे घोटालों से होने लगी है। समाज की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था, हर पहलू पर इतनी नाकामी क्यों हासिल हो रही है? इससे बढ़कर चिंता की बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार इन सारे विषयों पर एकदम चुप है। क्या जनता के विकास के ये सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर सरकार की प्राथमिकता से बाहर हो गए हैं? ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने जमीनी सच्चाई से पूरी तरह पीठ फेर ली है और प्रदेश को उसके हाल पर छोड़ कर, खुद सिर्फ झूठी ब्रांडिंग से अपनी पीठ थपथपाने में व्यस्त हो गई है। हकीकत से मुंह फेर कर मोहन सरकार झूठे प्रचार-प्रसार में मस्त है। जबकि चुनावों के पहले बीजेपी ने बड़े-बड़े वादे कर जनता को गुमराह करने का काम किया। आज प्रदेश की जनता खुद सरकार से सवाल करना चाहती है कि वादों का क्या हुआ? सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर अपनी गाड़ी को चला रही है। और सपने ऐसे दिखाए जा रहे हैं कि प्रदेश ने विकास के कई सोपान गढ़ लिए हैं।

दलितों पर अत्याचार

पिछले एक साल में प्रदेश में दलितों पर काफी अत्याचार हुए हैं। वह चाहे शिवपुरी की घटना हो या सागर की घटना हो। सारे प्रदेश में दलितों पर हो रहे अत्याचारों से यही लगता है कि यह साल दलित अत्याचार पर केन्द्रित रहा है। दलितों का मसीहा बताने में बीजेपी ने भले ही कोई कोर कसर नहीं छोड़ी हो लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर पर दलितों की क्या स्थिति है, यह बताने की जरूरत नहीं है। कोई दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन प्रदेश में दलितों पर अत्याचार की घटना नहीं होती हो। शिवपुरी के इंदरगढ़ में एक दलित युवक की लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। मध्यप्रदेश के सागर जिले के ग्राम बरोदिया नोनागिर में दलित युवती द्वारा छेड़छाड़ की शिकायत से गुस्साए गुंडों ने युवती के भाई नितिन अहिरवार की पिछले वर्ष अगस्त माह में हत्या कर दी थी। हत्या में बीजेपी नेताओं की संलिप्तता सामने आई थी। पीड़ित परिवार समझौते के लिये तैयार नहीं हुआ तो दो दिन पूर्व पीड़िता के चाचा राजेंद्र अहिरवार की भी हत्या कर दी गई। मंदसौर जिले के एक गांव में एक महिला का पीछा करने के आरोप में दलित व्यक्ति को चेहरा काला करके, गले में जूतों की माला डालकर घुमाया गया। इन घटनाओं के बाद एक बार फिर साबित हो गया था कि प्रदेश में दलित वर्ग सुरक्षित नहीं है। यह दोनों घटनाएं तो सिर्फ ऐसी थी जो सुर्खियों में ज्यादा रहीं लेकिन ऐसी न जाने हजारों घटनाएं हैं जो रोज दलितों से साथ घटती रहीं। भाजपा के शासन में दबंगों के हौसले बढ़ रहे हैं और दलित तथा आदिवासियों के अत्याचार छीनना उनकी आदत बन गई है। दुर्भाग्य की बात है मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इस तरह के विषयों पर कुछ भी कहने से बचते रहे और दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने में पूरी तरह नाकाम रहे। और दलितों की सुरक्षा सुनिश्चित कराने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं।

कर्ज के भरोसे सरकार

मध्य प्रदेश में कर्ज दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा कोई महीना नहीं बीतता है जब सरकार कर्ज न ले रही हो। यह सरकार अब कर्ज के भरोसे हो गई है। सरकार पिछले 11 महीनों में 40 हजार 500 करोड़ रुपये का कर्ज ले चुकी है। राज्य यादव सरकार के एक साल पूरे होने के साथ कर्ज का आंकड़ा 52.5 हजार करोड़ तक पहुंचने वाला है। दिसंबर 2023 से अब तक सरकार ने 47.5 हजार करोड़ का कर्ज लिया है। साल 2024 के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज 4 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। पिछले 6 माह में हर महीने 05-05 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 में अब तक 30 हजार करोड़ का कर्ज लिया जा चुका है। 31 मार्च 2025 तक मप्र सरकार का कर्ज 4.21 लाख करोड़ पहुंचेगा। मौजूदा वित्त वर्ष में सरकार अपनी जरूरतों के लिए लगभग 25 हजार करोड़ का अतिरिक्त कर्ज लेगी। पिछले साढ़े चार साल में मप्र सरकार पर कर्ज का बोझ सबसे तेजी से बढ़ा है। मार्च 2020 की स्थिति में सरकार पर लगभग 2.01 लाख करोड़ का ही कर्ज था, लेकिन पिछले साढ़े चार साल में यह दोगुना हो गया है। साढ़े चार साल में सरकार अब तक करीब 02 लाख करोड़ का कर्ज ले चुकी है।

वादे पूरे करने में नाकाम मोहन सरकार

सरकार अपने कार्यकाल का 01 साल पूरा होने का जश्न मना रही है। लेकिन अपने वादों को भूल गई है। चुनावों के समय जो वादे किये थे उन पर ध्यान ही नहीं है। लाडली बहनों को 3,000 रुपये की राशि देने का वादा, किसानों को उपज का दाम मिलना, युवाओं को रोजगार देने का वादा, महिलाओं को सुरक्षा देने का वादा, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने का वादा ऐसे तमाम वादे थे जो एक साल में शुरू ही नहीं हुए हैं।

किसान परेशान, जश्न में सरकार

मध्य प्रदेश में खाद की कमी के कारण किसानों की आय पर भी काफी असर पड़ा है। किसानों ने खाद की कमी के कारण अपनी फसल ही नहीं बोई। किसानों को ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पहले साल के कार्यकाल में ऐसे मामले हैं जहां मोहन यादव की सरकार बैकफुट पर नजर आई।

राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल

13 दिसंबर 2023 को मोहन यादव राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। मोहन यादव के पहले कार्यकाल में मध्य प्रदेश में क्राइम के कई ऐसे मामले आए जिसके राज्य सरकार की किरकिरी हुई। वैसे तो प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है लेकिन प्रदेश में दिनोंदिन बढ़ रहे अपराधों ने मध्यप्रदेश को बदनाम किया है। अपराधों के आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। क्या महिलाएं क्या बच्चियां, कोई सुरक्षित नहीं है। साइबर क्राइम भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है।

नौकरियों की घोषणा पर भर्ती नहीं

राज्य के युवाओं को साधने के लिए मोहन यादव की सरकार ने एक लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की थी। दिसंबर महीने से भर्ती शुरू होनी थी लेकिन कई विभाग ऐसे हैं जो यह रिपोर्ट तक नहीं दे पाए हैं कि उनके विभाग में कितने पद खाली हैं। बीते एक साल से भर्ती नहीं होने पर युवाओं में ओवरएज होने का डर है।

नर्सिंग घोटाला से धूमिल हुई छवि

राज्य में नर्सिंग घोटाले के बाद प्रदेश सरकार की छवि धूमिल हुई है। राज्य में कॉलेजों की संख्या कम की गई है। नर्सिंग घोटाले सामने आने के बाद समय पर परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं। पूरे मामले की निगरानी कोर्ट में चल रही है। सरकार ने पूरे मामले में लीपापोती कर हजारों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की है। राज्य के कई छात्र संगठन भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं।

किसानों की धान खरीदी का वादा पूरा नहीं

छत्तीसगढ़ की तरह मध्य प्रदेश में धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये देने की घोषणा की गई थी। लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद भी धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपये नहीं किया गया। धान अभी भी 2320 रुपये के समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। इसके साथ ही किसानों को खाद के लिए के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जिलों में खाद की कमी को लेकर किसान सड़कों पर उतर चुके हैं।

गूगल ने विलो क़्वांटम चिप बनाकर तकनीक के क्षेत्र में किया कमाल

प्रमोद भार्गव
वरिष्ठ पत्रकार

प्रमोद भार्गव

गूगल ने वर्ष 2024 के अंतिम माह दिसंबर में विलो नाम की क़्वांटम चिप बनाकर तकनीक के क्षेत्र में बड़ा हल्ला मचा दिया है। अत्यंत सूक्ष्म महज 4 वर्ग सेंटीमीटर की यह चिप एक तरफ तो 30 साल से भी ज्यादा पुरानी समस्या का हल खोजने में सक्षम है, वहीं यह चिप 5 मिनट में ऐसे कार्य कर सकती है, जिन्हें करने में सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को भी 10 सेप्टिलियन अर्थात अरबों साल लग सकते हैं। अतएव इससे कृत्रिम बुद्धि, फ्यूजन ऊर्जा तथा ब्रह्मांड के तारामंडल के गृह-नक्षत्रों को जानने में मदद मिलेगी। मौसम व प्राकृतिक आपदाओं की सटीक भविष्यवाणी करने में सुविधा होगी। तकनीक के क्षेत्र में इस नवीन उपलब्धि की सर्वत्र चर्चा है। एलन मस्क जैसे लोग इस उत्पाद को लेकर अचंभित हैं। इसलिए इसे सुपर ब्रेन की संज्ञा दी जा रही है। विलो चिप व्यावसायिक रूप में क़्वांटम कंप्यूटिंग की नई दिशा तय करती हुई मील का पत्थर साबित होगी।

दुनिया में इस समय दिन दूनी, रात चौगुनी गति से प्रगति हो रही है। कुछ समय पहले तक असंभव सी लगने वाली चीजें आज प्रौद्योगिकी की मदद से सरलता से परिणाम तक पहुंच रही हैं। एक समय संगणक के विकास ने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किया था। अब कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) ने चिकित्सा से लेकर हथियारों के निर्माण तक हर क्षेत्र में कंप्यूटर और रोबोट के प्रयोग को नया आयाम दिया है। पारंपरिक कंप्यूटर की दुनिया में इस प्रगति के समानांतर एक और अनुसंधान चल रहा है, जिसका नाम है 'क्वांटम कंप्यूटिंग' यानी अति-सूक्ष्मता का विज्ञान। भारत ने भी अब इस क्षेत्र में गति लाने का ऐलान कर दिया है। भौतिक-शास्त्र के क्वांटम सिद्धांत पर काम करने वाली इस कंप्युटिंग में असीमित संभावनाएं देखी जा रही हैं। शोध के लिहाज से यह विषय किसी के लिए भी रुचि का विषय हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार एक पूर्ण विकसित क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा आंकी जा रही है। इस क्वांटम कंप्यूटिंग या मैकेनिक्स की खास बात यह है कि इसकी शुरुआत के बाद भारतीय और पश्चिमी वैज्ञानिक यह मान रहे हैं कि भारतीय भाववादी सिद्धांत को जाने बिना अणु या कण में चेतना का आकलन नहीं किया जा सकता। क्वांटम भौतिकी और कृत्रिम बौद्धिकता एक तरह से चेतना के भाववादी सिद्धांत को ही अस्तित्व में लाने के उपाय हैं।

क्वांटम कंप्युटिंग या यांत्रिकी एक लैटिन शब्द है। इसका अर्थ अतिसूक्ष्म कण है। इस विषय के अंतर्गत पदार्थ के अति सूक्ष्म कणों का अध्ययन किया जाता है। इनमें परमाणु, न्यूक्लियस एवं इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन सभी मौलिक कणों का अध्ययन शामिल है। इसमें इनके व्यवहार और उपयोगिता का अध्ययन किया जाता है। इस नवीन विषय के अध्ययन की नींव 1890 में वैज्ञानिक मैक्स प्लांक ने डाली थी। हालांकि इस समय तक वैज्ञानिक यह मानकर चल रहे थे कि भौतिकी में जितने नियमों का आविष्कार होना था, लगभग हो चुका है। अब केवल इन नियमों को प्रत्येक जगह क्रियान्वित करना भर शेष है। किंतु कुछ प्रश्न तब भी ऐसे थे, जिनके हल खोजे नहीं जा सके थे। अभी तक काले पिंड (बॉडी) के सतत वर्णक्रम (स्पेक्ट्रम) के भिन्न-भिन्न भागों की ऊर्जा के वितरण को परिभाषित नहीं किया जा सका था। इसे समझने के लिए प्लांक ने प्रकाश उत्सर्जन करने वाले द्रव्य-कणों की निरंतर चाल के साथ उनमें बिखरी ऊर्जा को भी समझने का विचार दिया। इससे काले पिंड के वर्णक्रम की व्याख्या सुलझ गई। दरअसल इस सोच के परीक्षण में जो निष्कर्ष आए, उनसे ज्ञात हुआ कि ऊर्जा का विकिरण लगातार न होकर टुकड़ों-टुकड़ों में होता है। इन टुकड़ों को विकिरण-कण नाम दिया गया। यह विकिरण भी कणों पर नहीं, बल्कि तरंगों के आधार पर चलता है। यह नियम विद्युत चुबंकीय सिद्धांत के विपरित था, क्योंकि अब तक यह माना जाता था कि द्रव्य-कणों की गति में विद्यमान ऊर्जा निरंतर गतिशील रहती है। यानी क्वांटम सिद्धांत के तहत अणु, परमाणु और इनके भी मूलभूत कण बेहद लघुतम अवस्था में मौजूद रहते हैं। इस खोज पर 1918 में मैक्स प्लांक को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1924 में सत्येंद्रनाथ बोस ने प्लांक के विकिरण नियम को समझाने के लिए एक सर्वथा नवीन विधि सुझाई। उन्होंने प्रकाश की कल्पना द्रव्यमानरहित कणों के एक गैस पिंड के रूप में ली। इसे फोटॉन गैस के रूप में मान्यता मिली। बाद में इस मान्यता को अल्बर्ट आइंस्टीन ने भी स्वीकृति दी।

विज्ञान ने पहले परमाणु को ही ऐसा सबसे सूक्ष्मतम कण बतलाया था, जिसने विश्व का निर्माण किया है। फिर आगे की खोज से ज्ञात हुआ कि परमाणु भी विभाजित हो सकता है। यानी उसे और अत्यंत सूक्ष्म-कणों में बांटा जा सकता है। फलतः ये सूक्ष्म-कण, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाम के लघुतम रूपों में सामने आए। कालांतर में कण मसलन क्वांटम भौतिकी और विकसित रूपों में सामने आई। तब पता चला कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को और विभाजित किया जा सकता है। अंततः इसे क्वार्क व लैपटॉन जैसे सूक्ष्मकणों में विभाजित कर भी लिया गया। इस तरह से कण भौतिकी में एक प्रामाणिक प्रतिदर्श सामने आया, जिसमें क्वार्क व लैप्टॉन के बारह सूक्ष्मतम कणों के प्रकार दर्ज हैं। इन्हें जरूर अब तक अविभाज्य माना गया है। अब इन्हें ही मूलकण माना जा रहा है। आधुनिक विज्ञान में यह धारणा बन रही है कि पदार्थ से संबंधित अत्यंत कम द्रव्यमान वाले, इन्हीं मूल कणों से सृष्टि के जड़ एवं चेतन स्वरूप अस्तित्व में आए हैं।

कण-यांत्रिकी को कल के कंप्यूटर का भविष्य माना जा रहा है। यह परमाणु और उप परमाणु के स्तर पर ऊर्जा और पदार्थ की व्याख्या करती है। पारंपरिक कंप्यूटर बिट (अंश) पर काम करते हैं, वहीं क्वांटम कंप्यूटर में प्राथमिक इकाई क्यूबिट यानी कणांश होती है। पारंपरिक कंप्यूटर में प्रत्येक बिट का मूलाधार या मूल्य शून्य और एक (एक) होता है। कंप्यूटर इसी शून्य और एक की भाषा में ही कुंजी-पटल (की-बोर्ड) से दिए निर्देश को ग्रहण करके समझता है और परिणाम को अंजाम देता है। वहीं क्वांटम की विलक्षणता यह होगी कि वह एक साथ ही शून्य और एक दोनों को ग्रहण कर लेगा। यह क्षमता क्यूबिट की वजह से विकसित होगी। परिणामस्वरूप यह दो क्यूबिट में एक साथ चार मूल्य या परिणाम देने में सक्षम हो जाएगा। एक साथ चार परिणाम स्क्रीन पर प्रगट होने की इस अद्वीतीय क्षमता के कारण इसकी गति पारंपरिक कंप्यूटर से कहीं बहुत ज्यादा होगी। इस कारण यह पारंपरिक कंप्युटरों में जो कूट-रचना या गूढ़-लेखन कर दिया जाता है, उससे कहीं अधिक मात्रा में यह कंप्यूटर डाटा ग्रहण व सुरक्षित रखने में समर्थ होगा। इसीलिए दावा किया जा रहा है कि इसकी मदद से आंकड़ों और सूचनाओं को कम से कम समय में प्रसारित किया जा सकेगा। एआई, जीपीटी चेट और चैटबॉट जैसी तकनीक इसकी सहायता से और तेजी से गतिशील रहेंगी। लेकिन विलो चिप निर्माण कर लिए जाने की घोषणा ने सुपर कंप्यूटर के निर्माताओं को फिलहाल सकते में डाल दिया है। क्योंकि विलो चिप की क्षमताएं ब्रह्मांड व्यास की तरह शक्तिशाली और असीमित बताई गई हैं।

क्वांटम कंप्यूटर की क्षमता को देखते हुए इसके विकास में भारत समेत अनेक देश लगे हैं। यही वजह है कि आविष्कार से पहले इसकी क्षमताओं का मूल्यांकन कर लेने वाले देश इसके अनुसंधान पर बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं। चीन ने 15 अरब डॉलर खर्च करने की घोषणा की है। चीन की ई-कॉमर्स कंपनी अलीबाबा अलग से इस पर काम कर रही है। यूरोपीय यूनियन ने इस क्षेत्र में करीब 8 अरब डॉलर खर्च कर रही है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में शोध को बढ़ावा देने के लिए क्वांटम सूचना-विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्था का गठन तो पहले ही कर लिया था, लेकिन केवल क्वांटम तकनीक पर नवीन शोध और आविष्कार के लिए 2023-24 से 2030-31 तक चलने वाले इस अभियान पर इस 6003.65 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। भारत इतनी बड़ी धनराशि पहली बार खर्च कर रहा है।

फिलहाल ऐसा भी माना जा रहा है कि क्वांटम यांत्रिकी का क्षेत्र जितना महत्वपूर्ण है, उस तुलना में इस क्षेत्र में कुशल युवाओं की संख्या बहुत कम है। एक अनुमान के मुताबिक दुनियाभर में एक हजार से भी कम लोग क्वांटम अभियांत्रिकी या भौतिकी में शोधरत हैं। अनेक कंपनियां कल्पनाशील एवं योग्य लोगों की तलाश में है। हैरानी इस पर भी है कि इस क्षेत्र में भविष्य की आपार संभावनाएं होने के बावजूद इस जटिल विषय की ओर युवा आकर्षित नहीं हो रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि कुशाग्र बुद्धि वाले जो विद्यार्थी कल्पनाशील विचार रखते हैं, उन्हें हतोत्साहित किया जाकर इस मेधा-शक्ति को कंपनियों के पारंपरिक कार्यों में खपाया जा रहा है या सरकारी नौकरियां करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस हश्र का सामना क्वांटम भौतिकी के जनक मैक्स प्लांक को भी करना पड़ा था और गूगल के बिल गेट्स को भी। जब प्लांक दसवीं कक्षा के छात्र थे, तब उन्होंने 15 वर्ष की आयु में इस विषय पर काम करने का विचार अपने गुरू को दिया, तो उनका उत्तर था, 'भौतिकी में अब नए आविष्कारों की संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं। इसमें जितना शोध व अनुसंधान होने की संभावनाएं थीं, वे पूरी हो चुकी हैं। अतः इस विचार को छोड़ दो। 'किंतु यह मैक्स की ही दृढ़ इच्छा-शक्ति थी कि उन्होंने अपने विचार को शोध के रूप में आगे बढ़ाया और क्वांटम भौतिकी को जन्म दिया। अब यही क्वांटम भौतिकी कंप्युटर की क्वांटम यांत्रिकी बन रही है। विलो चिप को इस कंप्यूटर का सुपर ब्रेन माना जा रहा है। यह भी कहा जा रह है कि इस क्षेत्र में जो देश बढ़-चढ़ कर नेतृत्व करेगा, वही दुनिया पर शासन भी करेगा।

विलो-चिपः क़्वांटम कंप्यूटर में क्रांति

रेवाराम पटेल ज़ी की स्मृति में विशाल निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया

-अमित राजपूत

जगत प्रवाह. देवरीकला। श्री सदुरू सेवा संघ ट्रस्ट ने पूज्यनीय स्व. रेवाराम पटेल जी की स्मृति में एक विशाल निशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का ग्राम मुआर की पंचायत में आयोजन किया। इस शिविर में लगभग 95 व्यक्तियों का नेत्र परीक्षण किया गया और 19 व्यक्तियों को नेत्र आपरेशन के लिए चित्रकूट के सदुरु नेत्र चिकित्सालय के लिए रवाना किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य समाज के वंचित और गरीब वर्ग के लोगों को निशुल्क नेत्र सेवाएं प्रदान करना था। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि मोती गौंड ने कहा, "हमारा उद्देश्य समाज के हर वर्ग के लोगों को स्वस्थ और सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।" इस शिविर में विशेषज्ञ डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों ने अपनी सेवाएं प्रदान कीं। इस आयोजन के लिए स्थानीय, और ग्रामीण और सामाजिक लोगों का सहयोग लिया। इस आयोजन की सफलता के लिए ट्रस्ट के सभी सदस्यों और सहयोगियों को बधाई दी। कार्यक्रम के आयोजनक गौरी पटेल,सहयोगी, राजकुमार दीवान जनपद सदस्य, अभिषेक राजपूत सरपंच मुआर,श्याम मनोहर पटैल, सुभाष पटैल ग्रामीण मौजूद थे। (जगत फीचर्स)

हिमालय बचेगा तो गंगा बहेगी

पर्यावरण की फिक्र
डॉ. प्रशांत सिन्हा
पर्यावरणविद्

हिमालय, जिसे 'धरती का मुकुट' कहा जाता है, न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक धरोहर है। यह पर्वत श्रृंखला लगभग 2,400 किलोमीटर में फैली हुई है और इसमें 15,000 से अधिक ग्लेशियर मौजूद हैं। यही हिमालय गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र जैसी अनेक नदियों का उद्गम स्थल है। इनमें गंगा सबसे महत्वपूर्ण है, जिसे करोड़ों भारतीयों की जीवनरेखा माना जाता है। परंतु, हिमालय और गंगा दोनों ही आज गहरे संकट में हैं। हिमालय से गंगा सागर तक गंगा से मिलने वाली सभी नदियों से पूरे देश का 60 प्रतिशत जल मिलता है। अब यह जल पिछले पांच दशकों से लगातार कम हो रहा है। गोमुख ग्लेशियर प्रति वर्ष 3 मीटर पीछे जा रहा है। कभी बर्फ अधिक तो कभी कम पड़ती है लेकिन पिघलने की दर उससे दोगुना हो गई है। हिमालय की बर्फ का तेजी से पिघलने का सिलसिला सन 1987 से अधिक तेज हुआ है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और अनियंत्रित विकास ने इनकी संरचना को गंभीर खतरे में डाल दिया है। यह संकट केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन और भविष्य का प्रश्न है।

हिमालयी ग्लेशियर, जो गंगा जैसी नदियों को पानी उपलब्ध कराते हैं, आज तेजी से पिघल रहे हैं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट (ICIMOD) की 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार, यदि ग्लोबल वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रहती है, तो भी हिमालय के ग्लेशियरों का एक तिहाई हिस्सा इस सदी के अंत तक गायब हो सकता है। यदि ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह बढ़ती रही, तो यह नुकसान 50% तक पहुंच सकता है। ग्लेशियरों के पिघलने से गंगा जैसी नदियों में अस्थायी तौर पर पानी का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे बाढ़ जैसी आपदाएं अधिक होंगी। उदाहरण के लिए, 2013 में उत्तराखंड में आई केदारनाथ बाढ़, जिसमें लगभग 5,700 लोग मारे गए, इसी असंतुलन का परिणाम थी। दीर्घकालिक प्रभावों में पानी की कमी और लाखों लोगों की कृषि पर निर्भरता का संकट पैदा हो सकता है।

गंगा पर संकट बढ़ता जा रहा है। इस पवित्र नदी पर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। गंगा लगभग 2,525 किलोमीटर लंबी है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। यह नदी 40% भारतीय जनसंख्या, यानी लगभग 50 करोड़ लोगों की जीवनरेखा है। गंगा न केवल सिंचाई और पीने के पानी का स्रोत है, बल्कि इससे लाखों लोग आजीविका भी कमाते हैं। परंतु आज यह नदी गंभीर प्रदूषण की चपेट में है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) की 2022 की रिपोर्ट के अनुसार, गंगा के 80% प्रदूषण का कारण नगरों और उद्योगों से निकलने वाला अनुपचारित सीवेज है। लगभग 2.9 बिलियन लीटर गंदा पानी हर दिन गंगा में गिराया जाता है, जबकि उपचार की क्षमता केवल 1.2 बिलियन लीटर प्रतिदिन की है।

औद्योगिक कचरे, प्लास्टिक और धार्मिक कचरे ने गंगा के पानी को इतना दूषित कर दिया है कि कई स्थानों पर इसे पीने या स्नान के लिए भी सुरक्षित नहीं माना जाता। गंगा के प्रदूषण का सीधा असर स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। गंगा किनारे रहने वाले लोगों में त्वचा रोग, पाचन तंत्र से जुड़ी बीमारियां, और यहां तक कि कैंसर जैसे रोगों के मामले बढ़ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, गंदे पानी के कारण हर साल लगभग 1.4 मिलियन लोग भारत में अपनी जान गंवाते हैं।हिमालयी क्षेत्र में अनियंत्रित खनन, वनों की कटाई, और बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य इस संकट को और गंभीर बना रहे है। 2015 से 2022 के बीच, हिमालयी क्षेत्र में वनक्षेत्र में 6% की कमी दर्ज की गई। चारधाम परियोजना जैसी सड़क निर्माण योजनाओं ने बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित किया है। जलविद्युत परियोजनाओं ने नदियों के प्रवाह को बाधित किया है। हिमालयी क्षेत्र में 50 से अधिक जलविद्युत परियोजनाएं बन रही हैं, जो नदी के प्राकृतिक प्रवाह और जैव विविधता पर गहरा प्रभाव डाल रही हैं।

गंगा और हिमालय एक दूसरे पर निर्भर है। हिमालय का अस्तित्व गंगा के प्रवाह और गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अनिवार्य है।

जायसवाल निवास पर पधारकर कंप्यूटर बाबा ने कुंभ मेले का आमंत्रण दिया

-प्रमोद बरसले

जगत प्रवाह. टिमरनी। देश की धार्मिक नगरी प्रयागराज महाकुंभ 2024-25 मेले में देश भर के अजब गजब साधु संत जुट रहे हैं और लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी वहां पहुंच रहे हैं। देश के साधु संतों में बड़ा ही उत्साह नजर आ रहा है इसी को आज नगर टिमरनी में देखा गया जहां इंदौर वाले स्वामी नामदेव दास त्यागी उर्फ कंप्यूटर बाबा वार्ड नंबर 10 में निवासरत नगर परिषद के पूर्व अध्यक्ष अरुण जायसवाल के निवास पर पधारकर प्रयागराज महाकुंभ मेले में आने का आमंत्रण दिया। जहां शाल श्रीफल से स्नेह पूर्वक बाबा का स्वागत किया गया। बाबा इंदौर से होते हुए टिमरनी पहुंचे और बड़े ही उत्साह के साथ वह महाकुंभ मेले का आमंत्रण देने हेतु आगे बढ़ रहे हैं। बाबा पूर्व में महामंडलेश्वर के पद पर भी विराजमान रहे उन्हें शिवराज सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री का पद भी मिला था। कंप्यूटर बाबा स्वामी नामदेव त्यागी उन धार्मिक नेताओं में से एक हैं जिन्हें राज मंत्री का दर्जा दिया गया था, आपने गौ हत्या को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और गौ माता को राजमाता का दर्जा देने का आवाहन किया। बाबा लैपटॉप, हेलीकॉप्टर, फेसबुक के शौकीन हैं। राजनीति और सोशल मीडिया पर भी बने रहते हैं। वार्ड नंबर 10 के लोगों ने बाबा का स्वागत किया। इस दौरान युवक कांग्रेस जिलाध्यक्ष राहुल जायसवाल ओम सोलंकी विष्णु नामदेव गिरीश घुरे जितेंद्र सोनकिया नप पार्षद हीरा घुरे अन्नु नायर बंटी रहड़वा राजेश योगी नाथ बाबा एवं वार्ड क्रमांक 10 के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। (जगत फीचर्स)

शराब की तस्करी, जखीरा सहित एक आरोपी पुलिस गिरफ्त में

-नरेन्द्र दीक्षित

जगत प्रवाह. नर्मदापुरम। प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा धार्मिक नगरी नर्मदापुरम में नर्मदा नदी के 5 किलो मीटर के क्षेत्र में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया हुआ है जिसके बाद से राजनीतिक रसूखदार हावी हो गई हैं। शराब का अवैध कारोबार मुख्यालय पर जोरों पर है जिसको लेकर पिछले दिनों जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा अवैध शराब पर कार्रवाई के सख्त निर्देश जिला प्रशासन को दिए हुए हैं। उसके बाद भी विभाग के जवाबदारों की लचर कार्य शैली के कारण देशी विदेशी शराब पर पुख्ता कार्यवाही नहीं हो पा रही है। पुलिस अधीक्षक डॉ. गुरकरन सिंह द्वारा सिटी कोतवाली सहित देहात पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए हुए हैं। इसी तारतम्य में मुखबिर से निरंतर मिल रही सूचना पर सिटी कोतवाली टीआई सौरभ पांडे व उनकी टीम के द्वारा 3 दिन के अथक प्रयासों के बाद बुधवार रात्रि अल्टो कार को सर्किट हाउस घाट रोड के पास घेराबंदी कर पकड़ा गया। इस दरमियान दो शराब तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।

दिनांक 25.12.24 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई कि अवैध शराब से भरी हुई एक ग्रे रंग की कार सर्किट हाउस घाट तरफ आने वाली है, सूचना को गंभीरता से लेते हुये थाना कोतवाली की पुलिस टीम द्वारा मुखबिर के बताये अनुसार स्थान पर नजर रखी गई, कुछ देर बाद एक ग्रे रंग की कार पुलिस को आती दिखी जिसे घेराबंदी कर रोकने का प्रयास किया । कार चालक ने पुलिस को देखकर कार को अंधेरे मे रोक दिया जिससे उक्त कार में बैठे हुये दो व्यक्ति कार से उतरकर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। पुलिस द्वारा उक्त कार की तलाशी ली गई जिसमे 16 पेटी अँग्रेजी शराब कीमती करीबन 1,69,000/- रु की होना पाया गया। कार चालक से उसका नाम, पता पूछा जिसने अपना नाम आयुष तिवारी पिता लेवेन्द्र तिवारी उम्र 25 वर्ष निवासी हर्बल पार्क नर्मदापुरम का होना बताया एवं उक्त शराब के संबंध मे बताया कि शिरीब गुरब एवं अस्सू पठान दोनों निवासी नर्मदापुरम द्वारा उक्त शराब नये साल पर बेचने के लिये ला रहे थे। कार से भागने वाले दो व्यक्ति भी शिरीष गुरब एवं अस्सू पठान ही है। पुलिस द्वारा मौके पर अवैध अँग्रेजी शराब 140 लीटर एवं ऑल्टो कार क्रमांक MP04ZQ5654 कुल कीमती लगभग 5,00,000/-रु को जप्त किया जाकर आरोपी 1. आयुष तिवारी 2. शिरीष गुरब एवं 3. अस्सू पठान के विरुद्ध धारा 34(2) आंबकारी अधिनियम का अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी शिरीष गुरब एवं अस्सू पठान फरार है, जल्द ही गिरफ्तारी की जावेगी। ज्ञात हो कि शिरीष गुरब के विरुद्ध वर्ष 2024 लोकसभा चुनाव के दौरान भी धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गयी थी।

(जगत फीचर्स)

RO No : 13057/195

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक विजया पाठक द्वारा जेयन आफसेट वर्क्स, पुल बोगदा भोपाल 462023 (मप्र) से मुद्रित तथा एफ-116/17, शिवाजी नगर, भोपाल (मप्र) से प्रकाशित। संपादक : विजया पाठक।
RNI-MPBIL/2011/39805 समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एट के तहत जिम्मेदार। (सभी विवादों का न्यायक्षेत्र भोपाल रहेगा।)